



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक तीन-निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2017/3050

स्थान दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

6/4/18

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र०क० 280/2015-16 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 5-8-17 के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक को ग्राह्यता एवं प्रचलनशीलता पर सुना जा चुका है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 5-8-17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक द्वारा शासकीय व आम रास्ते की भूमि सर्वे क्रमांक 649 रकबा 2.70 हैक्टर के अंश भाग 11x8 वर्गफुट पर दुकान निर्माण करके अतिक्रमण किया गया है। आम-रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण के कारण तहसीलदार चितरंगी ने प्रकरण क्रमांक 38/13-14 अ 68 में पारित आदेश दिनांक 22-1-17 से आवेदक पर 1500/-रु. अर्थदण्ड अधिरोपित करके बेदखली के आदेश दिये हैं, जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई एवं अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी ने अपील प्र०क०75/15-16 में आवेदक की सुनवाई की है तदुपरांत आदेश दिनांक 7-7-16 पारित करके अपील निरस्त की है।

आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा द्वारा आवेदक की सुनवाई करके अपील प्रकरण क्रमांक 1224/15-16 को आदेश दिनांक 30-7-16 से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त कर दिया।

आवेदक ने इस आदेश को पुनरावलोकन में लेने हेतु संहिता की धारा 51 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 280/2015-16 पुनरावलोकन दर्ज करके आवेदक की सुनवाई की है एवं पारित आदेश दि0 5-8-17 से पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 280/2015-16 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 5-8-17 तथा अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 75/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-16 में विवेचित किये गये तथ्यों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि आवेदक ने शासकीय व आम रास्ते की भूमि सर्वे क्रमांक 649 रकबा 2.70 हैक्टर के अंश भाग 11x8 वर्गफुट पर दुकान निर्माण करके अतिक्रमण किया है जिससे आम रास्ते की अर्थात् सार्वजनिक हित की भूमि बाधित हुई है जिसके कारण आवेदक किसी प्रकार का अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। तहसीलदार चितरंगी के आदेश दिनांक 22-1-17 में, अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के आदेश दिनांक 7-7-16 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पुनरावलोकन आदेश दिनांक 5-8-17 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है फलतः निगरानी में सुनवाई पर्याप्त आधार न होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य